However, implementation of Family Planning Programme is slow in States of Assam, Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh among major states. The major reasons for slow implementation have been inadequate priority by State leadership, slow progress in education particularly among women and their status in the society and week accountability of health functionaries.

बालिका मृत्यु दर

*365. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ बालिकाएं अपना जन्मदिवस भी नहीं मना पाती है, उनमें से 25 प्रतिशत बालिकाएं अपना पांचवा जन्मदिन भी नहीं मना पाती और इनमें से एक-तिहाई बालिकाएं एक वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही मर जाती है,

(ख) क्या 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में 3.13 करोड़ ज्यादा थी,

(ग) क्या यह भी सच है कि गांवों में महिलाओं के प्रति भेदभाव अधिक है, और

(घ) यदि हां, तो गांवों में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा आयोजित नमूना पंजीकरण पद्धति के अनुसार तीन वर्षों में 5 वर्ष से कम आयु के बालकों तथा बालिकाओं की मृत्यु दर इस प्रकार है:

वर्ष	कुल	बालक	बालिकाएं
1994	23.9	23.6	24.2
1995	24.2	23.2	25.3
1996	23.9	22.2	25.6

पिछले तीन वर्षों के दौरान शिशु मृत्यु दर इस प्रकार है:—

वर्ष	कुल	बालक	बालिकाएं
1994	74	75	73
1995	74	73	76
1996	72	71	73

(ख) 1991 की जनगणना के अनुसार, पुरुषों तथा महिलाओं का अनुपात इस प्रकार है:—

जनसंख्या		
पुरुष	महिलाएं	अनुपात
43.92 करोड़	40.70 करोड़	927

(ग) और (घ) इस ब्यान का वास्तविक सत्यापन नहीं हो सकता किन्तु सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के दर्जे तथा स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे:—

1. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास (ड्वाकश)
2. जवाहर रोजगार योजना।
3. इन्दिरा आवास योजना।
4. समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम।
5. सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम।
6. शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठ्यक्रम।
7. प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता।
8. आयोत्पादक कार्यक्रमों हेतु रोजगार स्कीम (नोराड)
9. ग्रामीण महिला विकास तथा शक्ति-सम्पन्नता परियोजना।
10. बालिका समृद्धि योजना।